

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की।
- सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपों में पर्यावरणीय शासन और तटीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला है।
- वन विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय मैग्रोव कार्यशाला का कल समापन हो गया।
- भारतीय खेल प्राधिकरण ने 'फिट इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल – कार निकोबार 2026' का आयोजन किया।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष के संदर्भ में स्थिति और चल रहे तथा प्रस्तावित राहत उपायों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति-सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने कहा कि यह संघर्ष लगातार बदलती हुई स्थिति है और इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में प्रभावित है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकार के सभी अंग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। उन्होंने राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भी कहा ताकि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी न हो। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और सचिवों के एक समूह के गठन का निर्देश दिया जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ समर्पित रूप से काम करेगा। बैठक के दौरान कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, निर्यातक, शिपिंग, व्यापार, वित्त, सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्यम, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रों में अपेक्षित प्रभाव और उससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों पर चर्चा की गई।

<><><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपों में पर्यावरणीय शासन और तटीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डाला है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने लिखे पत्र में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और CRZ अधिसूचना, 2019 के मौजूदा ढांचे में एक बुनियादी कमी की ओर इशारा किया है। उन्होंने अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन, डीजल आधारित बिजली पर निरंतर निर्भरता, सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन के

बुनियादी ढांचे में कमी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में हो रही समस्याओं का मुद्दा उठाया है। सांसद ने 'परफॉरमेंस-बेस्ड कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम' का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए हवाई किराए को तर्कसंगत बनाए जाने और पर्यटकों पर रुकने की अवधि के आधार पर 'आइलैंड सस्टेनेबिलिटी शुल्क' लगाए जाने पर जोर दिया।

<><><><><><><><>

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 'पशु औषधि विक्रय केंद्र' खोलने की योजना शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सस्ती, जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं उपलब्ध कराना है। पंजीकृत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियां, जिनके पास कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह, एक पंजीकृत फार्मासिस्ट और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से दवा बिक्री का लाइसेंस हो, पात्र हैं। प्रत्येक राजस्व ब्लॉक में केवल एक केंद्र की ही अनुमति होगी। सरकार इस योजना में संचालकों को वित्तीय सहायता के तहत आकांक्षी जिलों, पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपसमूह और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र खोलने पर 1.5 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। केन्द्र में केवल भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा आपूर्ति की गई दवाएं ही बेची जा सकेंगी। बिलिंग के लिए आधिकारिक Point-of-Sale सिस्टम का उपयोग अनिवार्य है। इन केंद्रों पर एथनो-वेटेनरी उत्पाद और प्रमाणित पशु आहार भी बेचे जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये, जबकि आकांक्षी क्षेत्रों के लिए निशुल्क है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से [pashuaushadhi.dahd.gov.in](http://pashuaushadhi.dahd.gov.in) पर किए जा सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश [dahd.gov.in](http://dahd.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

<><><><><><><><>

वन विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय मैग्रोव कार्यशाला का कल समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में छात्रों और शोधकर्ताओं से मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ विकसित करने का आग्रह किया, जो न केवल विभिन्न जीवन रूपों का आधार है बल्कि स्थानीय आजीविका में भी सहायक है। कार्यक्रम में वन आनुवंशिकी संस्थान, कोयंबटूर के डॉ. बी. नागराजन, वैज्ञानिक-जी विशिष्ट अतिथि थे। कार्यशाला के दौरान पांच विषयों पर सत्र आयोजित किए गए जिसमें तटीय सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के शमन में मैग्रोव की भूमिका, मैग्रोव जैव विविधता और उससे जुड़ा समुद्री जीवन, मैग्रोव वनों में ईको-टूरिज्म की संभावनाएं, मैग्रोव बहाली की तकनीकें और सर्वोत्तम अभ्यास तथा सामुदायिक भागीदारी और मैग्रोव से जुड़े आजीविका के अवसर



